

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत सभी उप-सचिवों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, चाहे वे उच्चतम न्यायालय में काम कर रहे हों अथवा किसी अन्य स्वायत्त निकायों में या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त योजना किन्-किन निकायों और कार्यालयों पर लागू नहीं होगी ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्षा) :** (क) भारत सरकार के उप सचिवों तथा अन्यत्र समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए भारतीय लोक-प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी जैसे संस्थानों में कार्यकारी विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। तथापि, ये कार्यक्रम उच्च उत्तरदायित्व वाले पद के अधिकारियों से सीधे सम्बन्धित नहीं है। प्रशासन सुधार आयोग ने वरिष्ठ प्रबन्धक पदों के लिये अनेक प्रस्तावों के सुझाव दिये हैं, जो कि विचाराधीन हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

### हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग

3054. श्री रामावतार शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री 22 अगस्त, 1969 के अतारंकित प्रश्न संख्या 4541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मंत्रालयों और विभागों के क्या नाम हैं जिन्होंने राजभाषा (संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने और उसके अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त सचिव के पद के अनुरूप एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है ;

(ख) उन मंत्रालयों के क्या नाम हैं जिन्होंने हिन्दी के विकास की प्रगति के बारे में और कार्यालयों में इसके अधिकाधिक प्रयोग के सम्बन्ध में अब तक प्रगति रिपोर्ट नहीं

भेजी हैं ; और उन्होंने इसके क्या कारण दिये हैं ; और

(ग) क्या अब तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों का ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्षा) :** (क) संचार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव अथवा उससे ऊंचे पद वाले वरिष्ठ अधिकारी को राजभाषा (संशोधन) अधिनियम के उपबन्धों तथा इस सम्बन्ध में जारी किये गये प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संचार विभाग में, जहां संयुक्त सचिव का कोई पद नहीं है, एक निदेशक इस कार्य की देखभाल करता है, और संसदीय कार्य विभाग में, जहां उप सचिव को उक्त कार्य सौंपा गया है, सचिव संयुक्त सचिव के पद का है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) जैसा कि दिसम्बर, 1967 में संसद द्वारा राजभाषा के सम्बन्ध में पारित सरकारी संकल्प के अधीन अपेक्षित है, हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रगामी प्रयोग में गति लाने के लिये बनाए गए कार्यक्रम सम्बन्धी 1968-69 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट 29 अगस्त, 1969 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी। सन् 1969-70 की दूसरी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट छपते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायगी।

### Implementation of Recommendations of National Integration Council

3055. SHRI YASHPAL SINGH :  
SHRI SITARAM KESRI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the action taken by the Centre and the

States on the recommendations of the National Integration Council at its Srinagar meeting to check communalism and regionalism ;

(b) the number of communal incidents that occurred in the first nine months of this year along with the names of the States ; and

(c) the details of the progress made in the implementation of Council's decisions on education and mass media to fight communalism and regionalism ?

THE MINISTER OF STATE (SHRI-MATI NANDINI SATPATHY) : (a) and (c). A statement (I) indicating the latest position regarding the progress made in the implementation of the recommendations of the National Integration Council on communal, regional, educational and mass media aspects laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT—4462/70.*]

(b) Information received from the State Governments is furnished in statement II laid on the Table of the House. [*Placed in Library See No. LT—4462/70.*]

#### **Willingness of Former Rulers for Settlement with Government**

3056. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether about 100 former privy purse holders, falling mostly in the lower brackets, have indicated to the Central Government their willingness to arrive at a settlement ;

(b) if so; the details thereof ;

(c) whether Government have decided that those former princes, who have volunteered to sign an agreement on transitional allowance, should be paid the entire amount ;

(d) if so, whether this amount would be paid in lumpsum ; and

(e) the decision taken by Government about those former princes who were getting higher privy purses ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS OF ELECTRONICS AND SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (a) to (e). Some former Rulers have been placing their views regarding transitional arrangements before Government from time to time. As already announced, the Government propose to make transitional payments to the former Rulers to enable them to make necessary adjustments to the changed circumstances. The details have not yet been finalised.

#### **Export Position of British Government**

3057. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report published in the *Hindustan Times* dated the 8th November, 1970 to the effect that the British High Commissioner, Sir Morrice James, on the 6th November, 1970 expressed concern over the dwindling exports from his country to India ;

(b) if so, what is the export position of the British Government to India during the last three years ; and

(c) the reasons for fall of export of the U.K. Government to India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) Yes, Sir.

(b) Imports from U. K. into India which stood at Rs. 157 crores in 1967-68 declined to Rs. 128 crores in 1968-69 to Rs. 100 crores in 1969-70.

(c) The decline in imports from U. K. could be attributed to development of indigenous capacity in the various sectors of industry in India, import substitution programmes, change in the structure of our imports, and emergence of new and cheaper sources of supplies of the products needed by India.